Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

जनवरी (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार **3**

- डोर-टू-डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना 3
- बेगूसराय के दो रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण 3
- बिहार को जल्द जोड़ा जाएगा टेफकोफ पोर्टल से 4
- देश के तीन शीर्ष थानों में बिहार का अरवल महिला थाना शामिल 4
- इंस्पायर अवार्ड में चार रैंक फिसला भागलपुर 5
- देश के 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के 61 प्रखंड शामिल 5
- जीपीआर सर्वे में पटना सिटी में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिलने के संकेत 6
- पटना पहुँचा जर्मनी से मंगाया गया थ्री-डी डोम स्क्रीन 7
- पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन 7
- पीके शाही बने बिहार के नये महाधिवक्ता 8
- केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में विभिन्न खनिजों के खनन के लिये सात ब्लॉक का आवंटन किया 8
- पूर्व डीजीपी सिंघल केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बने 9
- पटना और मुजफ्फरपुर में जिओ टू 5जी सेवा लॉन्च 9
- बिहार में 1364 करोड़ रुपए की लागत से होगा कोयल नहर का निर्माण 9
- ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2022 10
- बिहार में पी.जी छात्राओं को मैटरनिटी लिव की मिलेगी पूरी छात्रवृत्ति 10
- जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले 200 किसानों को मिलेगा जिओ टैग 11
- पटना विश्वविद्यालय के छात्र जाबिर अंसारी ने अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा में जीता स्वर्ण 11
- बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण का पोर्टल लॉन्च 12
- भागलपुर में बना राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट 12
- बिहार पुलिस के दो जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 17 को सराहनीय पुलिस सेवा पदक 13
- बिहार के तीन विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित 14
- प्रधानमंत्री फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना (PMFME) में बिहार देश में पहले नंबर पर 15
- इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार बना अव्वल 15
- पटना के चार सरकारी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल होंगे स्वायत्त 16

नोट :

बिहार

डोर-टू-डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना

चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2023 को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित भारतीय रेलवे और डाक विभाग (बिहार सर्किल) के अधिकारियों और कारोबारियों की बैठक में बताया गया कि अब पटना के कारोबारियों को ट्रेन से अपना पार्सल (सामान) देश के किसी भी कोने में भेजने और प्राप्त करने के लिये रेलवे स्टेशन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इसके लिये डाक विभाग और भारतीय रेलवे मिलकर डोर-टू-डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार डोर-टू-डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना जनवरी के दूसरे सप्ताह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना-हावड़ा और पटना-पुणे रूट पर शुरू होगी। इसके तहत अब पोस्टमैन पार्सल को इस पर दिये गए पते पर पहुँचाएगा या लेने भी जाएगा।
- इस योजना के तहत पार्सल को बिना टूट-फूट के सुरक्षित पहुँचाया जाएगा। इसके लिये डाक विभाग ने बजाज एलयांज बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत पार्सल के कुल लागत का 30 फीसदी और जीएसटी प्रीमियम देकर बीमा भी करा सकते है।
- इसके तहत सौ फीसदी बीमा का लाभ कारोबारियों को मिलेगा। इसके अलावा कारोबारियों का पार्सल को बुकिंग स्थान पर 24 से 36 घंटे के बीच पहुँच जाएगा। इस योजना के तहत 35 से 100 किलो तक का पार्सल बुक किया जाएगा।
- सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सुविधा के उपयोग के लिये एक नंबर भी जारी किया जायेगा। इसके अलावा एप और वेबसाइट के जरिये भी पार्सल की बुकिंग और ट्रेकिंग की सुविधा दी जाएगी।
- ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट प्रणाली के तहत पार्सल कारोबारियों के घर से ही उठाया जाएगा। बुक करने के बाद रेलवे से उसका परिवहन होगा और फिर निर्धारित पते तक पहुँचाया जाएगा। पार्सल को कारोबारियों के घर से उठाने तथा बुकिंग का काम डाक विभाग करेगा। फिर उस पार्सल को रेलवे निर्धारित पते के पास के रेलवे स्टेशन तक पहुँचायेगा। इसके बाद डाककर्मी स्थानीय रेलवे स्टेशन से पार्सल उठाएगा और बुक हुए पते तक पार्सल को पहुँचाएगा।

बेगूसराय के दो रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण

चर्चा में क्यों ?

2 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिये 'अमृत भारत स्टेशन योजना' नाम से एक नयी नीति तैयार की है, जिसमें सोनपुर मंडल द्वारा चयनित 15 स्टेशनों की सूची में बिहार के बेगूसराय के दो स्टेशनों को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत बिहार के बरौनी-कटिहार रेलखंड पर स्थित लखमिनियाँ एवं साहेबपुर कमाल स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न प्रकार की उच्च क्षमता वाले नयी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ पहले से मौजूद सुविधाओं को भी उन्नत किया जाएगा।
- जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्ष में एक हजार से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिये नयी योजना विकसित की है। यह योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुन:विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा होगी।

नोट :

- योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों की मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिये विभिन्न चरणों में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करना है।
- स्टेशन पर नयी सुविधाओं की शुरूआत के साथ ही पुरानी सुविधाओं को भी इस योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना के तहत विभिन्न ग्रेड के प्रतीक्षालय को क्लब करने का प्रयास किया जाएगा और जहाँ तक संभव हो सकेगा अच्छा कैफेटेरिया और खुदरा सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म (760-840 एमएम) बनाए जायेंगे तथा प्लेटफार्मों की लंबाई आम तौर पर छह सौ मीटर की होगी। स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिये फाइव जी नेटवर्क के टावर लगाये जाएंगे।
- 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत महिलाओं और दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिये सभी श्रेणी के स्टेशनों पर महिलाओं और दिव्यांगों के लिये पर्याप्त संख्या में शौचालय बनाए जाएंगे। सड़कों को चौड़ा करके, अवांछित संरचनाओं को हटाकर, उचित रूप से डिजाइन किये गए साइनेज, पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिये सुविधाएँ रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
- इस योजना के तहत पुराने या बेकार भवनों का उपयोग उच्च प्राथमिकता यात्री संबंधी गतिविधियों के लिये किया जाएगा। वेटिंग रूम को छोटे-छोटे विभाजन के माध्यम से बाँटा जाएगा तथा स्टेशन पर एक्जीक्यूटिव लाउंज और छोटी व्यावसायिक बैठकों के लिये भी स्थान बनाए जाएंगे। स्टेशन यात्रियों को सुखद अनुभव कराने के लिये हरियाली तथा स्थानीय कला और सांस्कृतिक तत्त्वों से स्टेशन को सजाया जाएगा।

बिहार को जल्द जोड़ा जाएगा टेफकोफ पोर्टल से

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को बिहार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) के वरिष्ठ उप महानिदेशक गिरजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बिहार को जल्द से जल्द टेफकोफ (टेलीकॉम एनालेटिक्ल फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन) पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य के मोबाइल उपभोक्ता घर बैठे पता लगा सकेंगे कि आपके नाम पर कितने मोबाइल सिम कनेक्शन एक्टिव हैं तथा इनमें कितने फर्जी आईडी पर लिये गए और कब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- गिरजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि साइबर क्राइम और देश विरोधी एक्टिविटी में फर्जी सिमों का इस्तेमाल खासकर सूबे के सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल, रक्सौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी आदि इलाके में बड़े पैमाने पर किये जाने की सूचना आती रहती है।
- उन्होंने बताया कि टेफकोफ (टेलीकॉम एनालेटिक्ल फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन) पोर्टल को विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ा गया है।
- उल्लेखनीय है कि टेफकोफ पोर्टल की शुरुआत 2020 में आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। अभी तक आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा को टेफकोफ से जोड़ा गया है।
- डीओटी के वरिष्ठ उप महानिदेशक ने बताया कि जिस स्टेट में यह पोर्टल शुरू करना होता है, वहाँ का डेटा एकत्र कर टेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में दो- तीन माह का वक्त लगता है। एक- एक राज्य का चयन कर इसे लागू किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि पोर्टल पर आधार नंबर डालते ही मोबाइल धारक को यह पता चल जाएगा कि उसके नाम से कितने सिम एक्टिव हैं। पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता फर्जी तरीके से संचालित सिम कनेक्शन को बंद करा सकते हैं। इसके लिये कंपनी को अनुरोध करना होगा। उसके बाद संबंधित उपभोक्ता के मामले की गहन जाँच- पड़ताल की जाएगी और मामला सही पाए जाने पर फर्जी कनेक्शन को बंद कर दिया जाएगा।

देश के तीन शीर्ष थानों में बिहार का अरवल महिला थाना शामिल

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिये देश के शीर्ष तीन थानों में चुना है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अरवल महिला पुलिस थाने का चयन अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की तेज गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि देश के सर्वश्रेष्ठ तीन थानों में ओडिशा के गंजाम ज़िले का अस्का थाना और उत्तराखंड के चंपावत ज़िले का बनवास पुलिस थाना भी शामिल है।
- 20 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली मे आयोजित पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इन सभी पुलिस थानों के थानाध्यक्षों को पुस्कृत किया जाएगा। प्रथम तीन में किसे कौन-सी रैंकिंग मिलेगी, इसकी घोषणा भी उसी दिन होगी।
- सितंबर, 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने अरवल महिला थाने का निरीक्षण किया था। इस दौरान गृह मंत्रालय की टीम ने पुलिस थाने के रजिस्टर में लंबित मामलों की संख्या, उपलब्ध सुविधाओं की जाँच की और स्थानीय नागरिकों से फीडबैक भी लिये।
- अरवल महिला थाने में महिलाओं के लिये बैठने की व्यवस्था, महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों को खेलने के लिये सभी प्रकार की सुविधाएँ मौजूद हैं। इस पुलिस थाने में दिव्यांगों व वृद्धों के लिये रैंप भी बना हुआ है और महिला तथा पुरूष हवालात अलग-अलग हैं।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों के साथ व्यवहार आदि मानकों पर देश के शीर्ष थानों का निर्धारण करता है।

इंस्पायर अवार्ड में चार रैंक फिसला भागलपुर

चर्चा में क्यों ?

8 जनवरी, 2023 को बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के गुणवत्ता कोषांग के अपर मुख्य कार्यक्रम समन्वयक शिव कुमार ने बताया कि इंस्पायर अवार्ड में इस बार भागलपुर की रैंकिंग नीचे आ गई है, जबकि बीते साल में भागलपुर ने सूबे में तीसरा रैंक हासिल किया था।

प्रमुख बिंदु

- समन्वयक शिव कुमार ने बताया कि इस वर्ष भागलपुर ज़िले के 143 बच्चे चयनित हुए, इसके बाद भी भागलपुर को सूबे में सातवाँ रैंक प्राप्त हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को नवाचर के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष इंस्पायर अवार्ड का आयोजन किया जाता है।
- इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये बच्चों को आनलाइन निबंधन कराना पड़ता है। इस अवार्ड योजना में कोई भी छात्र नया और रचनात्मक आइडिया भेज सकता है। आइडिया का चयन नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता, पर्यावरण की अनुकूलता और वर्तमान तकनीक से बेहतरी के आधार पर किया जाता है।
- भागलपुर ज़िला के 1926 बच्चों ने इंस्पायर अवार्ड में आइडिया भेजा था। इसमें 143 बच्चों के आइडिया का चयन इंस्पायर अवार्ड के प्रथम चरण के लिये किया गया है। चयनित बच्चों को अब आइडिया के आधार पर मॉडल बनाने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से दस-दस हज़ार रुपए दिये जाएंगे।
- राज्य में नटखट साइंस लैब के मागदर्शन वाले सात विद्यालयों के 14 छात्र-छात्राओं का चयन इंस्पायर अवार्ड के पहले चरण के लिये किया गया है। इसमें उत्क्रमित उच्च विद्यालय खैरा भागलपुर, भवानी कन्या मध्य विद्यालय खंजरपुर, मध्य विद्यालय रामपुर, उर्दू मध्य विद्यालय चंपानगर, मदनलाल कन्या मध्य विद्यालय भागलपुर, मध्य विद्यालय नाथनगर नंबर वन आदि शामिल हैं।

देश के 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के 61 प्रखंड शामिल

चर्चा में क्यों ?

10 जनवरी, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरूआत की है। इसके लिये देश के पिछड़े 500 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विकास के कई पैमाने पर पिछड़े प्रखंडों को आगे लाने के लिये शुरू की गई आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के तहत प्रखंडों के चयन के लिये नीति आयोग ने एक मानक तय किया है। प्रखंडों का चयन करने के लिये नीति आयोग ने प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या को आधार बनाया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को 75% और जनसंख्या को 25% वेटेज दिया गया है। इसी आधार पर अलग-अलग राज्यों से प्रखंड का चयन किया गया है।
- बिहार के 27 पिछड़े ज़िलों में से 61 प्रखंड का चयन किया गया है। इसी प्रकार आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश से 68, झारखंड से 34 तथा ओडिशा व पश्चिम बंगाल से 29-29 प्रखंडों का चयन किया गया है।
- आकांक्षी ज़िले की तरह ही विकास के कई पैमानों पर पिछड़े इन प्रखंडों में स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास जैसे इंडीकेटर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इन ज़िलों के लिये केंद्र की ओर से अतिरिक्त फंड का भी प्रबंधन किया जाएगा। प्रखंडों की रैंकिंग की जाएगी ताकि उनमें आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा बढ़ सके।
- गौरतलब है कि वर्ष 2018 में लागू आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में बिहार के 12 ज़िले- कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा शामिल हैं।
- इन ज़िलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के लिये मुख्य रूप से स्कूल में पढ़ाई और लाइब्रेरी की सुविधा, स्कूलों में आधारभूत संरचना शामिल हैं।

जीपीआर सर्वे में पटना सिटी में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिलने के संकेत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की खोज करने के लिये ग्राउंड पेंट्रेटिंग राडर (जीपीआर) से सर्वे शुरू करवाया है। जिसमें प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिलने के संकेत मिल रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- जीपीआर सर्वे वर्तमान गुलजारबाग के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में आईआईटी कानपुर की टीम के द्वारा किया जा रहा है। इस टीम ने बताया कि गुलजारबाग के इर्द- गिर्द 490 बीसी-180 बीसी के बीच की ईंट की दीवार के संकेत मिल रहे हैं।
- इस सर्वे में 80 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक के नीचे अवशेष मिलने के संकेत मिले रहे हैं, जो अलग-अलग डायरेक्शन में हैं। इसमें बेगम की हवेली और बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज के नीचे भी अवशेष के संकेत मिल रहे हैं।
- दरअसल आर्किलोजीकल उत्खनन से पहले जीपीआर सर्वे में ऐतिहासिक अवशेष के सांकेतिक सिंग्लन मिलता है। इसी संकेत के आधार पर आर्किलोजीकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्खनन करता है।
- सर्वे में लगी टीम के अनुसार बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान के एक मीटर नीचे मल्टीस्ट्रक्चर अवशेष के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों की मानें, तो एक ऐसी टनल का साक्ष्य मिल रहा है, जो गंगा नदी की तरफ जाती होगी। इस सर्वे के 3डी प्रोफाइल में मौर्यकाल के एक मीटर से लेकर तीन मीटर तक के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं।
- गौरतलब है कि जीपीआर एक भू-भौतिकीय विधि है, जो सतह की छवि के लिये रडार का उपयोग करती है। यह पुरातात्त्विक महत्त्व के स्थलों जैसी भूमिगत उपयोगिताओं की जाँच करने के लिये उप सतह का सर्वेक्षण करने का एक तरीका है। सर्वे की इस अत्याधुनिक तकनीक से बिना खुदाई कराए ज़मीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियाँ आसानी से मिल जाती हैं। महत्त्वपूर्ण जगहें, जहाँ ऐतिहासिक धरोहरें दबी हो सकती हैं, वहाँ की खुदाई में इनके नष्ट होने का खतरा अधिक रहता है, लेकिन इस सर्वे में किसी तरह का नुकसान नहीं होता है।

नोट :

पटना पहुँचा जर्मनी से मंगाया गया थ्री-डी डोम स्क्रीन

चर्चा में क्यों ?

11 जनवरी, 2023 को जर्मनी से मंगाया गया नया थ्री-डी डोम स्क्रीन तारामंडल पटना पहुँच गया। इसके लगने से जल्द ही पटना के लोगों को तारामंडल में थ्री-डी स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने और समझने का अवसर मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- पटना के तारामंडल के आधुनिकीकरण की ज़िम्मेदारी जर्मन कंपनी कालजाइज को दिया गया है। अगले सप्ताह से कालजाइज व एनसीएसएम की टीम थ्री-डी डोम स्क्रीन के अलग-अलग पैनल को इंस्टॉल करेगी। इससे तारामंडल का प्रोजेक्शन सिस्टम पूर्ण रूप से डिजिटलाइज हो जाएगा।
- लगभग 34 करोड़ रुपए से आधुनिकीकरण होने से यहाँ सौरमंडल पर बनी वर्ल्ड क्लास फिल्में देख सेंकेगे। इसके साथ ही लेजर प्रोजेक्टर आरजीबी किरणों को कंप्यूटर के माध्यम से मिश्रित कर थ्री-डी शो के लिये वास्तविक रंगों का निर्माण करेगा।
- दर्शकों की सुविधा के लिये सीटिंग एरेंजमेंट में भी बदलाव किया जाएगा, जो पहले के मुकाबले और भी आरामदायक होगा।
- तारामंडल के प्रोजेक्ट एंड प्रोग्रामिंग डायरेक्टर अनंत कुमार ने बताया कि अगले सप्ताह से थ्री-डी स्क्रीन को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद साइड वॉल और सीटिंग एरेंजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह तक दर्शक यहाँ नये अंदाज में तारों की दुनिया से रूबरू हो सकेंगे।
- तारामंडल के आधुनिकीकरण के साथ ही यहाँ आने वाले विजिटर्स के लिये अलग से स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी तैयार की जाएगी। तारामंडल भवन के पहले तल्ले पर करीब 600 वर्गफुट में दो करोड़ रुपए से इस नयी गैलरी का निर्माण किया जाएगा। इस गैलरी में लोगों को अंतरिक्ष, गैलेक्सी, तारा और सौरमंडल के बारे में मल्टीमीडिया पैनल और इंटरेक्टिव प्रदर्शों के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
- स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी का डिजाइन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की टीम द्वारा किया गया है। गैलेरी के निर्माण में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एलइडी स्क्रीन, लेजर बेस्ड प्रोजेक्टर व अपडेटेड डिस्पले टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन

चर्चा में क्यों ?

12 जनवरी, 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का 75 वर्ष की आयु में गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- 1 जुलाई, 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बाबई गाँव में जन्मे, शरद यादव पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक उपचुनाव में लोकसभा के लिये चुने गए थे।
- शरद यादव 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे। उन्होंने 90 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में नागरिक उड्डयन और खाद्य और नागरिक आपूर्ति के पोर्टफोलियो को सँभालने वाले केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार सँभाला।
- वह जद (यू) के पहले अध्यक्ष थे और 2003 से 2016 तक इस पद पर रहे। मई 2018 में, उन्होंने बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण जद (यू) से अलग होने के बाद लोकतांत्रिक जनता दल (एलजेडी) लॉन्च किया। मार्च 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया।
- दस बार के सांसद (लोकसभा में सात बार और राज्यसभा में तीन बार) रहे शरद यादव को एक लंबे समय तक समाजवादी नेता के रूप में माना जाता था। वह राम मनोहर लोहिया के दर्शन से प्रेरित थे और जेपी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे।
- शरद यादव ने तीन राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता- मध्य प्रदेश में जबलपुर से दो बार, उत्तर प्रदेश में बदायूं से एक बार तथा बिहार में मधेपुरा से चार बार।

नोट :

पीके शाही बने बिहार के नये महाधिवक्ता

चर्चा में क्यों ?

13 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि प्रशांत कुमार शाही पूर्व अधिवक्ता ललित किशोर का स्थान लेंगे। ललित किशोर की पटना हाईकोर्ट में 21वें महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति 31 जुलाई, 2017 को हुई थी।
- एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही पूर्व में भी बिहार के महाधिवक्ता रह चुके है। वर्ष 2005 से 2010 तक वे राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल रहे। इन्हें नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। मंत्री पद से हटने के बाद वे फिर से पटना हाईकोर्ट में वकालत करने लगे।

केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में विभिन्न खनिजों के खनन के लिये सात ब्लॉक का आवंटन किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में ग्लूकोनाइट (पोटाश), क्रोमियम, निकेल सहित प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मैग्नेटाइट (आयरन), बॉक्साइट और दुर्लभ मृदा धातुओं के खनन के लिये सात ब्लॉक का आवंटन बिहार राज्य सरकार को किया है।

प्रमुख बिंदु

- इन खनिजों का खनन इसी साल शुरू होगा। इसके लिये इन सभी में खनन की मंज़ूरी का प्रस्ताव इसी महीने खान एवं भू-तत्त्व विभाग की तरफ से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पेश किया जाएगा। इसमें खनिज तत्त्वों से राज्य सरकार और खनन एजेंसी को होने वाले आय के संबंध में भी दिशा-निर्देश तय होगा।
- राज्य मंत्रिपरिषद की मंज़ूरी मिलते ही चार ज़िलों में मौजूद खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें रोहतास, गया, औरंगाबाद और जमुई शामिल हैं। सरकार इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिये 'एसबीआई कैप्स'की सेवा ले रही है।
- गौरतलब है कि खान एवं भू-तत्त्व विभाग ने एसबीआई कैप्स-निवेश बैंक और परियोजना सलाहकार से एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार सभी ज़िलों में करीब 20 हज़ार करोड़ रुपए के ग्लूकोनाइट और लौह अयस्क के भंडार को पट्टे के आधार पर खनन की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
- इससे पहले सर्वे में रोहतास ज़िले में करीब 25 वर्ग किमी. इलाके में ग्लूकोनाइट मिला था। इसमें ज़िले के नावाडीह प्रखंड में 10 वर्ग किमी., टीपा में आठ वर्ग किमी. और शाहपुर प्रखंड में सात वर्ग किमी. का इलाका शामिल है।
- इसके साथ ही गया और औरंगाबाद ज़िले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डेंजना और आसपास के इलाकों में करीब आठ वर्ग किमी. क्षेत्र में निकेल और क्रोमियम पाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि ग्लूकोनाइट (पोटाश) का बड़े पैमाने पर औषधि व रासायनिक खाद में इस्तेमाल होता है। निकेल का उपयोग लोहे व अन्य धातुओं पर परत चढ़ाकर उन्हें जंग लगने से बचाने के लिये किया जाता है। यह एक लौह चुंबकत्व रखने वाला तत्त्व है और इससे बने चुंबक कई उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं।
- इसके अलावा निकेल को इस्पात में मिलाकर उसे 'स्टेनलेस'(जंग-रोधक) बनाया जाता है, जबकि क्रोमियम का उपयोग मिश्रधातु बनाने में किया जाता है। स्टील को अधिक कठोर बनाने, चर्मशोधन में यह काम आता है। मानव शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करने में भी यह कारगर है। शीशे को हरा रंग देने, क्रोम प्लेटिंग समेत अन्य कार्यों में यह प्रभावी है। इसका उपयोग तेल उद्योग में उत्प्रेरक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जंग अवरोधक के रूप में किया जाता है।

नोट :

पूर्व डीजीपी सिंघल केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बने

चर्चा में क्यों ?

14 जनवरी, 2023 को बिहार राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को केंद्रीय चयन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप नियुक्त किया है। इसके लिये गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।

प्रमुख बिंदु

- परिषद के वर्तमान अध्यक्ष केएस द्विवेदी के कार्यकाल की विस्तारित अवधि 20 जनवरी, 2023 को पूरी हो जाएगी। इसके बाद सिंघल नए अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर लेंगे।
- सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिये एस के सिंघल को चयन पार्षद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 19 दिसंबर, 2022 को एसके सिंघल डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान अध्यक्ष केएस द्विवेदी को भी बिहार के डीपीपी के पद से रिटार होने के बाद सरकार ने यह जिम्मेवारी सौंपी थी। उन्हें छह महीने का अवधि विस्तार भी दिया गया था।
- केंद्रीय चयन परिषद बिहार पुलिस में सिपाही के पद के अलावा अन्य विभागों में नियुक्तियों के लिये भी परीक्षा का आयोजन करता है।
- संजीव कुमार सिंघल भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच अधिकारी हैं। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में एसके सिंघल को सरकारी प्रावधानों के अनुसार वेतन और सारी सुविधाएँ मिलती रहेंगी।

पटना और मुजफ्फरपुर में जिओ ट्रू 5जी सेवा लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

14 जनवरी, 2023 को बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर शहर में रिलायंस जियो ने अपनी ट्रू 5जी सेवाएँ लॉन्च कर दी।

प्रमुख बिंदु

- पटना के शहरी क्षेत्र पटना साहिब से लेकर दानापुर तक और मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में अब जियो ट्रू 5जी का कवरेज मिलेगा।
- कंपनी का दावा है कि दिसंबर 2023 तक बिहार और झारखंड के हर कस्बे और हर गांव में जियो ट्रू 5जी उपलब्ध होगा।
- कंपनी के अनुसार पटना और मुजफ्फरपुर में जियो उपयोगकर्ताओं को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जा रहा है। आमंत्रित यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 जीबीपीएस स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा।
- लांचिंग पर जियो प्रवक्ता ने कहा कि देश भर में ट्रू 5जी रोलआउट की स्पीड को हमने और तेज़ कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि साल 2023 में प्रत्येक जियो उपयोगकर्ता को जियो ट्रू 5जी टेक्नोलॉजी का फायदा मिले।
- जिन शहरों में ट्रू जी लॉन्च किया गया है, वे देश के महत्त्वपूर्ण पर्यटन-स्थल, व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रो में शामिल हैं।
- जियो की ट्रू 5जी सेवाओं के लॉन्च के साथ ही क्षेत्र के उपभोक्ताओं को न केवल सबसे अच्छा दूरसंचार नेटवर्क मिलेगा बल्कि इ-गवर्नेंस, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, हेल्थकेयर, कृषि, आईटी के क्षेत्रों में भी विकास के अवसर मिलेंगे।

बिहार में 1364 करोड़ रुपए की लागत से होगा कोयल नहर का निर्माण

चर्चा में क्यों ?

16 जनवरी, 2023 को बिहार के नवीनगर जल संसाधन विभाग के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार ने बताया कि बिहार में उत्तर कोयल नहर पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में डीपीआर तैयार किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- एग्जिक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार ने बताया कि डीपीआर तैयार करने के लिये औरंगाबाद के अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र प्रसाद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया था।

नोट :

- उन्होंने बताया कि 1364 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड व बिहार बॉर्डर के 103 आरडी से लेकर गया ज़िला स्थित नहर के अंतिम छोर तक 9 आरडी तक नहर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि संभावित मार्च-अप्रैल माह से उत्तर कोयल कैनाल से लेकर सभी डिवीजन के डिस्ट्रीब्यूटरी पुल-पुलिया व फॉल से लेकर कल्वर्ट आदि का कार्य शुरू हो जाएगा। नहर के लाइनिंग व पुनर्निर्माण होने से ज़िले के किसानों को धान व रबी की सिंचाई करने में सहूलियत होगी।

ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2022

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को जारी ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2022 के अनुसार बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की अंग्रेजी और गणित की क्षमता में इजाफा हुआ है, साथ ही निजी कोचिंग में बच्चों की रुचि बढ़ी है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति भी बढ़ी है, जबकि 15-16 साल की अनामांकित लड़कियों का अनुपात घटा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में कक्षा 5 के बच्चों में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता में वर्ष 2016 से 2022 के बीच 3% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2018 में ऐसे बच्चों की संख्या 18.1 थी, जो 2022 में 22.4% हो गई है।
- कक्षा 8 में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता 2022 में 2014 के समान ही 8% पर स्थिर है। इसी प्रकार राज्य में कक्षा 3 के 11.4 बच्चे अंग्रेजी के साधारण वाक्यों को पढ़ने में सक्षम और 54.5% बच्चे उनका अर्थ बताने में सक्षम थे।
- इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सरकारी या निजी स्कूलों के कक्षा 5के बच्चों में भाग करने की दक्षता वर्ष 2018 की तुलना में 5% बढ़ कर 2022 में 35.4% हो गई है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के ऐसे बच्चों की संख्या में 5.9% और कक्षा 8 में 2.4% की वृद्धि हुई है।
- कक्षा 8वीं तक के बच्चों में निजी कोचिंग के ट्रेंड 5% का इज़ाफा हुआ है। इस वर्ग के अंतर्गत 2018 में 62.2% बच्चे निजी ट्यूशन लेते थे, अब यह आँकड़ा 71.7% हो गया है।
- उल्लेखनीय है कि बिहार में निजी कोचिंग का ट्रेंड देश में सर्वाधिक है।
- कोविड के दौरान सरकारी स्कूल बंद होने के बाद भी 1% नामांकन बढ़े हैं। वर्ष 2022 तक बिहार के सरकारी स्कूलों में छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन 82.2% है। इसी आयु वर्ग में निजी और सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन 98% रहा है।
- वर्ष 2022 के दौरान बिहार में 11-14 वर्ष की अनामांकित लड़कियों की संख्या 8% रह गई है। 15-16 साल की अनामांकित लड़कियों का अनुपात घटकर 6.7% रह गया है। प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 2018 में 56.5% से बढ़ कर 2022 में 59.3% हो गई है। 30.2% प्राथमिक और 34.9% उच्च प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकें थीं।
- बिहार के स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक तीन वर्ष तक के नामांकित बच्चे - 1%
- बिहार में 60 या उससे कम विद्यार्थियों वाले प्राथमिक सरकारी स्कूल - 8%
- बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति 2018 में 68।5% की तुलना में बढ़ी - 9%
- गौरतलब है कि एक गैर-सरकारी संगठन 'प्रथम'इस रिपोर्ट को जारी करता है।

बिहार में पी.जी छात्राओं को मैटरनिटी लिव की मिलेगी पूरी छात्रवृत्ति

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों को एक नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार अब मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) करने वाली छात्राओं को मातृत्व अवकाश के बाद पढ़ाई पूरी करने में लगने वाले वक्त के लिये भी छात्रवृत्ति दी जाएगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) करने वाली छात्राएँ मातृत्व अवकाश में रहती हैं तो उनको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अब इन छात्राओं को मातृत्व अवकाश के बाद जितना समय पढ़ाई को पूरा करने में लगेगा, उस अवधि की छात्रवृत्ति उनको मिलेगी।
- विदित है कि पहले ऐसी छात्राओं को मानवीय आधार पर सिर्फ मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता था, पर उनको अपने तीन साल के कोर्स को बाद में पूरा करने के दौरान कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी।
- गौरतलब है कि पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली छात्राओं को जूनियर रेसिडेंट के रूप में छात्रवृत्ति दी जाती है। मातृत्व अवकाश के बाद उनको तीन साल की पढ़ाई पूरी करनी है। जितने दिन वह अवकाश में रहती हैं, उसका प्रशिक्षण उतने दिन बाद में पूरा किया जाना होता है। तीन साल के प्रशिक्षण के बाद ही उनको डिग्री दी जाती है।
- ज्ञातव्य है कि बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में तीन साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें विद्यार्थियों को पहले साल प्रति माह 68,545 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि द्वितीय वर्ष में प्रति माह 75,399 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिये जाते हैं। इसी तरह तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली छात्राओं को 82 हज़ार रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले 200 किसानों को मिलेगा जिओ टैग

चर्चा में क्यों ?

20 जनवरी, 2023 को बिहार के मुज़फ्फरपुर ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक धर्मेंद्र सिंह ने ज़िला उद्योग केंद्र में एक कार्यशाला के दौरान बताया कि मुज़फ्फरपुर में जैविक खेती से लीची का उत्पादन करने वाले 200 किसानों को जिओ टैग से जोड़ा जाएगा, जिस पर उनके उत्पादन से लेकर पूरा रिकॉर्ड होगा।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लीची का उत्पादन करने वाले किसानों को जिओ टैग से जोड़े जाने पर देश-विदेश कहीं से भी लोग जिओ टैग की बदौलत सीधा किसान से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिये 'एक ज़िला एक उत्पाद'के तहत लीची उत्पादान करने वाले किसानों के रिकॉर्ड के लिये ज़िला उद्योग विभाग की ओर से एक टीम भी बनाई गई है।
- विदित है कि 'एक ज़िला एक उत्पाद'का मुख्य उद्देश्य प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है। ऐसे में लीची की मार्केटिंग के लिये पूरी कार्य योजना तैयार की गई है।
- ज़िला उद्योग केंद्र की कार्यशाला के दौरान 'एक ज़िला एक उत्पाद'के तहत लीची की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को प्रेरित किया गया।
- इन्वेस्ट इंडिया की नचिकेता ने बताया कि लीची की जैविक खेती से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने ज़िले के छोटे किसानों को एक साथ मिल कर या फिर एफपीओ बनाकर लीची की खेती के बारे में जानकारी दी तथा लीची के बाग में हल्दी, सरसों, अदरक आदि की फसल के लाभ के बारे में भी बताया।

पटना विश्वविद्यालय के छात्र जाबिर अंसारी ने अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा में जीता स्वर्ण

चर्चा में क्यों ?

22 जनवरी, 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के छात्र जाबिर अंसारी ने इतिहास रचते हुए 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के तत्त्वावधान में 17-22 जनवरी, 2023 तक पाँच दिवसीय अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन कराटे महिला-पुरुष प्रतियोगिता बीआर यादव इंडोर स्टेडियम बहतराई में हुआ।
- इस प्रतियोगिता में देश के लगभग 200 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के 2500 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

नोट :

- कराटे के जाने-माने खिलाड़ी जाबिर अंसारी जमुई ज़िला के अंतर्गत झाझा प्रखंड के तुंबापहाड़ के निवासी हैं। वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं।
- विदित है कि हाल ही में पटना में आयोजित बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2023 में जाबिर अंसारी ने लगातार सातवीं बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। स्वर्ण पदक जीतने पर जाबिर का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिये हुआ है, जो कि 17 से 19 फरवरी, 2023 को देहरादून उत्तराखंड में आयोजित होना है।
- इसके अलावा जाबिर ने ओडिसा की राजधानी भुवनेश्वर में 22 से 25 दिसंबर, 2022 तक आयोजित 12वीं ऑल इंडिया ओपन नेशनल कराटे प्रतियोगिता में भी 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था।
- कराटे के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बिहार सरकार 3 बार राष्ट्रीय स्तर के खेल सम्मान से भी जाबिर को सम्मानित कर चुकी हैं। 11 दिसंबर, 2022 को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना में संकट हरण सहयोग समिति के द्वारा आयोजित महात्मा बुद्ध सम्मान से जाबिर को सम्मानित किया जा चुका है।

बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण का पोर्टल लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2022 को बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल को लॉन्च किया गया। यह पोर्टल जातीय सर्वेक्षण कार्य में सभी प्रकार के डिजिटल प्रबंधन के लिये उपयोगी होगा।

प्रमुख बिंदु

- बिहार में हो रही जाति गणना के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम चरण में एकत्रित किये गए सभी आँकड़ों को अब इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और ये आँकड़े मोबाइल एप पर द्वितीय गणना के समय प्रगणक और पर्यवेक्षकों को उपलब्ध होंगे। इसी के आधार पर दूसरे चरण की गणना होगी।
- जाति गणना के पहले चरण में राज्य भर में करीब दो करोड़ 58 लाख 90 हज़ार 497 परिवारों तक गणना कर्मियों ने पहुँच कर मकानों की नंबरिंग की।
- पहले चरण में परिवार के मुखिया का नाम और वहाँ रहने वाले सदस्यों की संख्या को अंकित किया गया था। सात जनवरी से शुरू हुए पहले चरण की जाति गणना में पाँच लाख 18 हज़ार से अधिक कर्मी लगाए गए थे।
- दूसरे चरण में एक से 30 अप्रैल तक जाति की गणना की जाएगी। इस चरण में लोगों से 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के नाम भी दर्ज किये जाएंगे।
- जाति गणना के लिये टोला सेवक, तालिमी मरकज, ममता, आशा कार्यकर्त्ता, जीविका दीदियाँ, शिक्षक, कृषि समन्वयक, मनरेगा कर्मी, रोज़गार सेवक और विकास मित्र को जिम्मेवारी दी गई है।

भागलपुर में बना राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट

चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को बिहार के भागलपुर ज़िले के नाथनगर के नूरपुर में वरीय अधिवक्ता अनिल झा ने बताया कि राज्य के लोगों के लिये हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिये भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। अब यहाँ से देश भर के कोर्ट की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि नाथनगर के नूरपुर में वरीय अधिवक्ता अनिल झा ने इसे बनवाया है। वरीय अधिवक्ता अनिल झा का दावा है कि बिहार में यह पहला कोर्ट है। अब तक किसी अधिवक्ता ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है। यह कोर्ट 10 डिसमिल यानी चार कट्ठे ज़मीन में बनाई गई है, जिसमे बड़ा सा हॉल बनाया गया है।

नोट :

- इसमें जज को बैठने के लिये इजलास बनवाया गया है। गवाहों की पेशी के लिये विटनेस बॉक्स (कटघरा) बनवाया गया है। इसके अलावा 65 इंच का एलसीडी लगवाया गया है। कंप्यूटर, कैमरा व अन्य डिजिटल मशीन लगवाई गई है। अब किसी भी कोर्ट के केस के लिये यहाँ बैठकर अधिवक्ता बहस कर सकेंगे।
- विदित है कि इस मूट कोर्ट में पहला केस आनलाइन दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लंबित चेक बाउंस से जुड़े मामले का लड़ा गया। इसे भागलपुर के शिकायतकर्त्ता प्रकाश शर्मा ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में केस किया था जिस पर सुनवाई हुई। इसके अलावा बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक्सिस बैंक में घुसकर दो करोड़ रुपए की बड़ी डकैती का केस अभियुक्तों की तरफ से लड़ा जा रहा है, इसकी सुनवाई मूट कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन चल रही है।
- अधिवक्ता अनिल झा ने बताया कि इस डिजिटल कोर्ट का उपयोग कोई भी अधिवक्ता कर सकेगा, जो हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ता है। उनके लिये यह मुफ्त सेवा है। इसके लिये एक एसोसिएशन बनाया जाएगा, जिसमें सक्रिय अधिवक्ताओं को जोड़ा जाएगा।
- सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट - पिछले तीन चार सालों से हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस की सुनवाई डिजिटल माध्यम से यानी ऑनलाइन होने लगी है। अधिवक्ता घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप में एप डाउनलोड कर सुनवाई में शामिल होते हैं। लैपटॉप और मोबाइल में सुनवाई में होने वाली परेशानी से समाधान के लिये वकील अपने या भाड़े के घरों में निजी फंड से डिजिटल कोर्ट बनवाते हैं। इससे अधिवक्ता और केस से जुड़े लोगों को हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट आना जाना नहीं पड़ता हैं।
- लॉ कंसल्टेंट राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मूट कोर्ट में नये-नये अधिवक्ताओं को सीखने का अच्छा अवसर मिलता हैं। नये अधिवक्ता बहस करने की अच्छी शैली सीखते हैं, हिचकिचाहट दूर होती है तथा दूर के कोर्ट का केस लड़ने में आसानी होती हैं।

बिहार पुलिस के दो जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 17 को सराहनीय पुलिस सेवा पदक

चर्चा में क्यों ?

26 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस के दो जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 17 को सराहनीय पुलिस सेवा पदक मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब यहाँ से किसी को पुलिस वीरता पदक नहीं मिला है।
- विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में गया ज़िला के नीमचक बथानी के एसडीपीओ विनय कुमार शर्मा और आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के इंस्पेक्टर विनय कृष्ण शामिल हैं।
- इसके अलावा आईजी से लेकर हवलदार तक के 17 कर्मियों को सराहनीय पुलिस सेवा पदक से नवाजा गया है। इनमें आईजी (मुख्यालय) विनय कुमार समेत अन्य शामिल हैं।
- इस पदक पाने वालों की सूची में सबसे ज्यादा संख्या सीआईडी और डुमरांव स्थित बीसैप (बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस) के कर्मी शामिल हैं।
- इन 17 को मिला सराहनीय पुलिस सेवा पदक-
  - विनय कुमार, आईजी (मुख्यालय), पुलिस मुख्यालय, बिहार
  - आलमनाथ भुईया, हवलदार, किशनगंज
  - अवधेश कुमार सिंह, हवलदार, बी-सैप - 4, डुमरांव, बक्सर
  - अक्षयबर नाथ पांडेय, कॉस्टेबल, बीसैप मुख्यालय, पटना
  - संजय कुमार शेखर, एएसआई, एटीएस, पटना
  - संतोष कुमार दीक्षित, एएसआई, सीआईडी, पटना
  - आलोक कुमार, कांस्टेबल, एससीआरबी, पटना

नोट :

- देवेंद्र कुमार, एएसआई, सीआईडी, पटना
- धर्मराज शर्मा, कांस्टेबल, पुलिस मुख्यालय
- धनंजय कुमार, कांस्टेबल - 107, सीआईडी, पटना
- बैजनाथ कुमार, कांस्टेबल, किशनगंज
- संजय कुमार, कांस्टेबल - 69, सीआईडी, पटना
- मुख्तार अली, कांस्टेबल - 217, सीआईडी, पटना
- बोअस एइंद, हवलदार, बीसैप - 4, डुमरांव, बक्सर
- पंचरत्न प्रसाद गोंड, हवलदार, बीसैप - 4 डुमरांव
- सिकंदर कुमार, हवलदार, बीसैप - 4, डुमरांव
- सत्येंद्र कुमार, हवलदार, बीसैप - 4 डुमरांव

- विदित है कि विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित विनय कुमार शर्मा वर्तमान में गया ज़िले के नीमचक बथानी अनुमंडल में एसडीपीओ के पद पर तैनात हैं। इन्हें अपनी 28 साल की सेवा के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कारण इस पदक से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 2017 में सराहनीय पुलिस सेवा पदक, 2018 में वीरता पुरस्कार और नक्सल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिये 2019 में आंतरिक सुरक्षा पदक प्रदान किया जा चुका है।

बिहार के तीन विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों 'पद्म पुरस्कारों'की घोषणा की। इनमें बिहार के तीन विभूतियों को पद्म श्री अवार्ड के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2023 के लिये राष्ट्रपति ने तीन द्वय मामलों (एक द्वय मामले में, पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है) सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है।
- सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएँ हैं और विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं।
- पद्म श्री पुरस्कार के लिये चयनित बिहार के तीन विभूतियों में सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद शामिल हैं।
- सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में जबकि आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये पद्म श्री अवार्ड हेतु चुना गया है।
- मधुबनी की सुभद्रा देवी पेपरमेसी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने इस कला को लोगों तक पहुँचाया। वहीं नालंदा के कपिलदेव प्रसाद ने बावन बूटी कला को एक पहचान दी है, उनके द्वारा इस कला से निर्मित साड़ियाँ काफी पसंद की जाती हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक गणितज्ञ होने के साथ-साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं।
- गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल है। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।
- यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं।
- असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म विभूषण', उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म भूषण'और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म श्री'से सम्मानित किया जाता है।
- ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किये जाते हैं जो आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाते हैं।

नोट :

प्रधानमंत्री फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना (PMFME) में बिहार देश में पहले नंबर पर

चर्चा में क्यों ?

27 जनवरी, 2022 को बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्त्वाकांक्षी उद्यमी योजना 'प्रधानमंत्री फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना (PMFME)' को लागू करने में बिहार देश में पहले नंबर पर है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक के मुताबिक अब तक देश में सबसे अधिक 450 लोन केस बिहार के मंज़ूर हुए हैं। पिछले दो वित्तीय वर्ष (2020-21 और 2021-22) में पूरे बिहार में मात्र 20 लोन केस मंज़ूर हो पाए थे। चालू वित्तीय वर्ष में बिहार में 2050 लोन स्वीकृत करवाने का लक्ष्य है।
- बिहार की तुलना में वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में अब तक महाराष्ट्र के 205 और तेलंगाना के 296 लोन केस स्वीकृत हो सके हैं। शेष राज्यों की स्थिति इससे भी कमज़ोर है।
- बिहार ने 16-23 जनवरी, 2023 के सप्ताह में पीएमएफएमई योजना के तहत बैंकों को सबसे अधिक आवेदन भेजे थे। हालाँकि, आवेदनों की तुलना में स्वीकृति दर कमज़ोर है।
- पीएमएफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण, जैसे- मिनी राइस मिल, फ्लॉवर मिल, अचार यूनिट, पापड़ यूनिट, मखाना यूनिट, नूडल/पास्ता यूनिट आदि को अधिक तवज्जो दी जाती है। इसमें भी 35 फीसदी तक का अनुदान दिया जाता है।
- पीएमएफएमई में बिहार के इन पाँच ज़िलों के सर्वाधिक केस स्वीकृत हुए- समस्तीपुर (46), नालंदा (30), पटना (24), मुज़फ्फरपुर (22) और सिवान (18)।
- इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को मदद देना भी है।
- इस योजना को पाँच वर्ष, यानी 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिये लागू किया गया है।

इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार बना अव्वल

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को इसरो के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बिहार अब न केवल अंधेरे से बाहर आ चुका है, बल्कि देश के चमकते राज्यों में अव्वल बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक दशक के भीतर नाइट टाइम लाइट्स में 43 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नाइट टाइम लाइट्स की वृद्धि में तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं, जिनमें सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण शामिल हैं।
- विदित है कि दुनिया भर के क्षेत्रों के आर्थिक विकास को ट्रैक करने के लिये अर्थशास्त्रियों द्वारा नाइट लाइट का उपयोग किया जाता है।
- पिछले दशक (2012 से 2021) के लिये इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) द्वारा तैयार किये गए नाइट टाइम लाइट (एनटीएल) एटलस के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 45% की वृद्धि हुई है, जबकि बिहार राज्य में यह वृद्धि 474% की रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत आगे हैं। राज्य की यह असाधारण उपलब्धि निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र में पिछले एक दशक में सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये व्यापक स्तर पर किये गए कार्यों का प्रतिफल है।
- बड़े राज्यों में पिछले एक दशक में बिहार के बाद यह वृद्धि केरल में 119% मध्य प्रदेश में 66%, उत्तर प्रदेश में 100% एवं गुजरात में 58% है।

नोट :

- ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने बताया कि इसरो द्वारा जारी किये डिकेडल चेंज ऑफ लाइफ टाइम लाइट (एनटीएल) ओवर इंडिया फ्रॉम स्पेस 2012 से 2021 के वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद तैयार किये गए हैं।
- उन्होंने बताया कि बिहार राज्य द्वारा जो 474% की वृद्धि प्रदर्शित की गई है, वह स्पष्ट करती है कि राज्य में 24×7 विद्युत उपलब्धता के लिये विद्युत कंपनियाँ लगातार प्रयासरत् हैं।
- आरएससी के द्वारा नासा एवं नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के आँकड़ों के आधार पर उपरोक्त सूचकांकों को तैयार किया गया है। एनआरएससी की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने साल 2012 से 2021 तक राष्ट्रीय स्तर और ज़िला स्तर पर लाइट में आए बदलाव को लेकर एक गहन स्टडी की है।

पटना के चार सरकारी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल होंगे स्वायत्त

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज़ पर राज्य के चार सरकारी सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों को स्वायत्तता मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- सरकारी सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों को स्वायत्तता देने से इन संस्थानों की सरकार पर निर्भरता कम होगी और बेहतर इलाज़, शैक्षणिक गतिविधियाँ एवं विकास करने की क्षमता विकसित होगी।
- जिन संस्थानों को स्वायत्तता देने की दिशा में पहल आरंभ की गई है, उनमें इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी), राजेंद्र नगर नेत्र रोग अस्पताल, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल और लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल, शास्त्रीनगर शामिल हैं।
- सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। पहले कागज़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें विभाग सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को परिभाषित कर रहा है।
- इसके अलावा स्वायत्त संस्थानों में शक्ति को परिभाषित किया जा रहा है, जिससे संस्थान को संचालित करने की शक्ति किन-किन पदों को सौंपी जाएगी, निदेशक की नियुक्ति किस विधि से की जाएगी और इन सभी स्वायत्त होने वाले संस्थानों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या शक्ति होगी और निदेशक की भूमिका क्या होगी आदि का निर्धारण होगा।
- इन सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों को स्वायत्तता देने के बाद विशेषज्ञों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति, दवा खरीदने की विधि, साफ-सफाई और सुरक्षा एजेंसियों की आउटसोर्सिंग कैसे की जाएगी। संस्थान को फीस निर्धारित करने की शक्ति क्या होगी, जैसे- मरीज़ के पंजीकरण, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जाँच, ओपीडी शुल्क या आईपीडी शुल्क क्या होगा। यह शुल्क मरीज़ों से लिया जाएगा या मुफ्त इलाज़ की सुविधाएँ दी जाएंगी आदि का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
- राजधानी के चारों अस्पतालों में डीएनबी कोर्स संचालित किया जाएगा। डीएनबी कोर्स में क्या सीट होगी और उनके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था होगी, इन सभी बातों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर काम शुरू हो गया है।

नोट :